



भारत के लिए एक आत्म-लक्ष्य

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III
(भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक - संतोष मेहरोत्रा (प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, श्रम केंद्र, जेनयू, नई दिल्ली)

13 दिसंबर, 2018

“नई जीडीपी बैंक सीरीज के बारे में प्रश्न उठाए जाने के कई वास्तविक कारण हैं।”

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) की अखंडता पर किसी भी तरह का सवाल न उठाते हुए, सबसे जानकार लोग यह पूछ रहे हैं कि यदि वर्ष 2004-2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण संकेतक बेहतर थे, तो अभी जारी किये गये आंकड़ों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कैसे इतनी उच्च है (2014 से प्रति वर्ष 7.4% और 2005-2014 में प्रति वर्ष केवल 6.7%)? यह उत्सुकता का भी केंद्र है, क्योंकि संशोधित पद्धति के तहत बैंक सीरीज तैयार करने के लिए गठित मंडल विशेषज्ञ पैनल, काउंटर-सहज ज्ञान संबंधी अनुमानों के साथ नहीं आया था जो अभी जारी किए गए हैं। उन्होंने बाजार की कीमतों पर औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 8.37% (2004-05 से 2008-09) और फिर 7.69% (2009-10 से 2013-14) पर अनुमान लगाया था।

संशोधन में तीन बदलाव हुए जो पहली बार 2015 में घोषित किए गए थे: सबसे पहला, आधार वर्ष में; दूसरा, बाजार मूल्य पर जीडीपी के लिए कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की पद्धति में (यह अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है और वर्तमान सरकार के दावे का आर है जिसका पालन सीएसओ ने किया है); और तीसरा, कंपनी आउटपुट / राजस्व का आकलन करने की विधि में, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए 21) द्वारा एकत्रित नए आंकड़ों का उपयोग करके अधिक विस्तृत तरीके से किया गया है।

नई श्रृंखला पर सवाल

एमसीए 21 वर्ष 2008 से उपलब्ध है लेकिन संभवतः इससे पहले उपलब्ध नहीं था। यह समस्या का एक स्रोत हो सकता है। एक अन्य संभावित स्रोत यह हो सकता है कि सीएसओ ने एक डिफ्लेटर का उपयोग किया जो पिछली श्रृंखला के लिए अलग था। लेकिन निम्नलिखित वास्तविक कारणों से नई सकल घरेलू उत्पाद श्रृंखला पर कई सवाल उठते हैं।

2004-05 से 2013-14 तक निरंतर कीमतों पर कृषि वृद्धि दर बहुत अधिक थी। लगातार दो सूखे साल (2014 और 2015) के बावजूद, नीतियां बिल्कुल सहायक नहीं रही हैं। हर साल किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? 2007-08 के अंत में त्रैवार्षिक के लिए 100 के आधार पर कृषि उत्पादन सूचकांक 2013-14 में 129.8 हो गया था। लेकिन गिरने के बाद, 2017-18 में यह मुश्किल से 130 हो गया। कृषि, गैर-कृषि अनौपचारिक क्षेत्र की तरह, पहली बार विमुद्रीकरण के कारण और दूसरी बार खराब तरीके से लागू किये गये वस्तु एवं सेवा कर के कारण ध्वस्त हो गई। दोनों उपायों ने आउटपुट के साथ-साथ रोजगार को प्रभावित किया, खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधा हिस्सा है और सभी निर्यात का आधा हिस्सा है।

निर्यात में पिछले 10 वर्षों की तुलना में पिछले चार वर्षों में काफी खराब प्रदर्शन हुआ है। वर्ष 2002-03 में निर्यात केवल 50 बिलियन डॉलर थे, लेकिन 2010-11 में यह 250 अरब डॉलर और 2013-14 में 315 अरब डॉलर तक पहुंच तक पहुंच गया था। जो वर्ष 2017-18 में भी उस स्तर तक नहीं पहुंचे सका।

जीडीपी में निवेश दो अवधि के बीच आर्थिक प्रदर्शन में अंतर का सबसे गंभीर स्रोत है। 2003-04 में, 1950-51 में भारत की बचत दर सकल घरेलू उत्पाद के 9.5% से बढ़ गयी थी और यह 25.9% थी। इसके बाद यह तेजी से बढ़ते हुए 36.8% तक पहुंच गया, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में वृद्धि के कारण, जो भारत के आर्थिक इतिहास में अभूतपूर्व था और तब से अभी तक इसे हासिल नहीं किया जा सका है।

इस बढ़ती बचत दर ने जीडीपी अनुपात में निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि में योगदान दिया, जो 2007-08 में 36.8% पर पहुंच गया, जो 2002-03 में सकल घरेलू उत्पाद का 23.8% से उच्च था। फिर वैश्विक आर्थिक संकट के चलते जीडीपी में निवेश गिर गया। लेकिन 2010-11 में, यह अभी भी सकल घरेलू उत्पाद का 34% था। 2011-12 की श्रृंखला में, नई सरकार, जिसे 2013-14 में 31.3% के निवेश/जीडीपी का हिस्सा विरासत में मिला था, उसने आंकड़े को 2014-15 में 30.4%, 2015-16 में 29.3% तक, 27.1% वर्ष (अस्थायी अनुमान) और 2017-18 में 26.4% तक गिरने दिया। यहाँ सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए था कि निवेश मुख्य रूप से विकास को प्रेरित करता है।

धीमी वृद्धि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी, जिसमें विनिर्माण, खनन, बिजली शामिल है) में रुझानों के अनुरूप है। जहाँ एक तरफ आईआईपी 2004-05 में 100 से बढ़कर 2013-14 में 172 (2004-05 श्रृंखला में) हो गया था, वही दूसरी तरफ 2013-14 में यह 100 के आधार पर (बाद की श्रृंखला में) 2013-14 में 107 हो गया और 2017-18 में केवल 125.3 हो गया। हाल ही में धीमी औद्योगिक उत्पादन को अन्य संकेतकों द्वारा भी सुझाव दिया गया है। 2004-05 और 2013-14 के बीच किसी भी वर्ष में बैंक क्रेडिट 14% से कम (सीमा 14.1 से 37%) बढ़ी। तब से, किसी भी वर्ष में बैंक क्रेडिट 10.9% (सीमा 8.2% से 13.9%) से आगे नहीं बढ़ा। प्लाट लोड फैक्टर (पीएलएफ या उत्पादन की जा सकने वाली अधिकतम ऊर्जा का वास्तविक ऊर्जा का अनुपात) 2004-05 से 2013-14 तक 68.5% औसत था और 2011 तक 74% से नीचे नहीं गिरा। इसके विपरीत, 2014-15 से 2017-18 तक पीएलएफ 57% हो गया है।



श्रम बल की स्थिति

गैरतलब हो कि गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि बहुत ही कम हुआ है जो वास्तव में वास्तविक अर्थव्यवस्था में अंतर को दर्शाती है। मेरे (लेखक) अनुमान के मुताबिक वर्ष 2004-05 और 2011-12 के बीच गैर-कृषि नौकरी की वृद्धि सालाना 7.5 मिलियन नौकरियाँ थीं, वो भी उस वक्त जब केवल 2 मिलियन श्रम बल में शामिल हो रहे थे।

साथ ही कृषि से 5 मिलियन से अधिक श्रमिकों ने गैर-कृषि कार्य के लिए खेती छोड़ दी। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब कृषि में श्रमिकों की पूर्ण संख्या गिर गई। हालांकि, बढ़ती मजदूरी (साथ ही तेजी से गैर-कृषि नौकरी की वृद्धि) ने 2004-05 और 2011-12 के बीच 168 मिलियन तक गरीबों की संख्या (तेंदुलकर गरीबी रेखा के अनुसार) को कम कर दिया, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी।

वर्ष 2004 से देखा जाये तो अधिकांश युवा बेहतर रूप से शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी गैर-कृषि नौकरियाँ नहीं बढ़ रही हैं। इस बीच, दुनिया ने पहले से ही हम पर हंसना शुरू कर दिया है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के एक टिप्पणीकार ने लिखा है कि मुझे डर है कि इस पूरे अभ्यास से भारत के विकास के आंकड़े पर विश्वसनीयता कम ना हो जाये।

GS World छींग

जीडीपी का बैंक सीरीज डेटा

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सरकार ने जीडीपी का बैंक सीरीज डेटा जारी किया है।
- इसमें ज्यादा सेक्टर शामिल किए गए हैं ताकि जीडीपी की गणना ठीक से हो और देश के सामने सही आंकड़े आए।
- सरकार ने 2004-05 के बदले जीडीपी का साल बदलकर 2011-2012 किया है।
- सीएसओ ने बैंक सीरीज आंकड़ों की गणना करते वक्त एक सांख्यिकी तकनीक स्प्लाइसिंग मेथड का इस्तेमाल किया है।

क्या है?

- चूंकि बेस ईयर बदला गया तो पुराने GDP आंकड़ों को नई बेस ईयर के हिसाब से संशोधित किया जा रहा है। ताकि इकोनॉमी को लेकर ज्यादा सटीक आंकड़े सामने आ सकें।
- इसके तहत इस बार वित्त वर्ष 2004-05 से 2011-12 तक के संशोधित आंकड़ों को जारी किया गया है।
- नए आंकड़ों में UPA कार्यकाल के दौरान 2010-11 के तहत जो GDP 10.3 फीसदी के पीक पर रही थी, वह अब 8.5 फीसदी पर आ गई है।
- इसी तरह 2011-12 में नई सीरीज से GDP ग्रोथ रेट घटकर 5.2 फीसदी रह गई, जो पुरानी सीरीज के आधार पर 6.6 फीसदी थी।
- इसी तरह 2007-08 के 9.8 फीसदी के ग्रोथ रेट के आंकड़े को घटाकर 7.7 फीसदी किया गया है।

क्या थी बेस ईयर बदलने की ज़रूरत?

- ऐसा इकोनॉमी में लगातार होते बदलावों के चलते किया गया। ताकि आर्थिक मोर्चे पर ज्यादा सटीक सूचना मिल सके।

▫ पुरानी 2004-05 बेस ईयर पर बेस्ट GDP आज के आर्थिक परिदृश्य की सही तस्वीर पेश नहीं कर पा रही थी।

▫ वहीं, नई बेस ईयर कॉरपोरेट सेक्टर के साथ असंगठित सेक्टर को लेकर भी बेहतर अनुमान लगाने में मद्दगार है।

क्या है 'स्प्लाइसिंग मेथड'?

- 'स्प्लाइसिंग' अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है दो टुकड़ों को लिंक करना।
- अर्थशास्त्र व सांख्यिकी में स्प्लाइसिंग मेथड का इस्तेमाल दो अलग-अलग आधार वर्षों पर जारी हुए जीडीपी आंकड़ों को लिंक करने के लिए किया जाता है।
- इस तकनीक में पुराने और नए आधार वर्ष के अनुपात के आधार पर पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आंकड़ों की गणना की जाती है।
- भारत में ही नहीं दुनिया के अन्य देशों जैसे हांगकांग, सिंगापुर, श्रीलंका और वियतनाम जैसे देश भी जीडीपी के बैंक सीरीज आंकड़ों की गणना के लिए स्प्लाइसिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं।

क्या है आधार वर्ष?

- जीडीपी की गणना किसी एक साल को संदर्भ वर्ष के रूप में लेकर की जाती है जिसे आधार वर्ष कहते हैं।
- वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है और इस पर जारी आंकड़ों को जीडीपी की नई सीरीज कहते हैं।
- नई सीरीज पर जीडीपी के आंकड़े 2011-12 के बाद के वर्षों के लिए ही उपलब्ध हैं, न कि पूर्व के वर्षों के लिए।
- इससे पूर्व आधार वर्ष 2004-05 था जिस पर जारी हुए आंकड़ों को जीडीपी की पुरानी सीरीज कहते हैं और ये 2013-14 तक उपलब्ध हैं।



संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: भारत में जीडीपी के आधार वर्ष में किये गये बदलाव का समालोचनात्मक विश्लेषण करें तथा नयी जीडीपी आकड़े समग्र विकास को किस प्रकार दर्शाते हैं? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

नोट : 12 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

